विनिवेश की स्थिति और प्राप्ति

प्रिलिम्स के लिये:

विनिवेश, DIPAM, CPSE, IPO

मेन्स के लिये:

विनिवेश की स्थिति और प्राप्ति।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने **51,000 करोड़ रुपए** का **विनिवेश** लक्ष्य निर्धारित किया है, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 21% कम है और संशोधित अनुमान से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए अधिक है। यह सात वर्षों में सबसे कम विनिवेश लक्ष्य भी है।

विनिवेश (Disinvestment):

- **परिचय:**
  - विनिवेश प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के **उद्यमों में रणनीतिक या वित्तीय खरीदारों को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है,** जिसे स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से या सीधे खरीदारों को शेयरों की बिक्री के माध्यम से किया जाता।
  - विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग विभिन्न **सामाजिक और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये एवं सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने** हेतु किया जाता है।
- **विधि:**
  - **अल्पांश विनिवेश (Minority Disinvestment):** इसमें सरकार कंपनी में बहुमत रखती है, आमतौर पर 51% से अधिक शेयर अपने पास रखती है ताकि प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
  - **बहुमत विनिवेश (Majority Divestment):** सरकार अधिग्रहण करने वाली इकाई को नियंत्रण सौंपती है लेकिन कुछ हिस्सेदारी बरकरार रखती है।
  - **पूर्ण निजीकरण:** कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को दिया जाता है।
- **प्रक्रिया:**
  - भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग **(Department of Investment and Public Asset Management- DIPAM)** द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
  - DIPAM का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में **सरकार के निवेश का प्रबंधन करना और इन उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश** की देख-रेख करना है।
  - सरकार ने वर्ष 2005 में **राष्ट्रीय निवेश कोष (National Investment Fund- NIF) का गठन किया था जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को चैनलाइज़ किया जाना था।**

विनिवेश की आवश्यकता:

- **राजकोषीय दबाव में कमी:** सरकार राजकोषीय दबाव को कम करने या **उस वर्ष हेतु राजस्व की कमी को पूरा करने के लिये विनिवेश कर सकती है।**
  - वह विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग **राजकोषीय घाटे** को वित्तपोषित करने, अर्थव्यवस्था और विकास या सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में निवेश करने एवं सरकारी ऋण चुकाने हेतु करती है।

- **निजी अभिरुचि को प्रोत्साहन:** विनिवेश संपत्ति निजी स्वामित्व और खुले बाज़ार में व्यापार को भी प्रोत्साहित करती है।
    - अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, **यह सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने हेतु संकेत देता है।**
    - इसके सफल होने पर अब सरकार को **घाटे में चल रही इकाई के घाटे को निधि देने की आवश्यकता नहीं होगी।**
- **कार्यकुशलता में सुधार:** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से हटकर सरकार इन उद्यमों की दक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार कर सकती है, क्योंकि निजी क्षेत्र का स्वामित्व और प्रबंधन नए विचारों एवं अधिक बाज़ारोन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है।
- **संसाधनों का बेहतर आवंटन:** सरकार विनिवेश के माध्यम से मुक्त संसाधनों को सामाजिक और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसी अन्य प्राथमिकताओं हेतु पुनः आवंटित कर सकती है।
- **पारदर्शिता:** विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कामकाज़ में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ा सकता है, क्योंकि **निजी क्षेत्र के स्वामित्व तथा प्रबंधन के तहत वित्तीय एवं परिचालन संबंधी रिपोर्टिंग अधिक सख्त हो सकती है।**

हाल के वर्षों में विनिवेश प्रदर्शन:

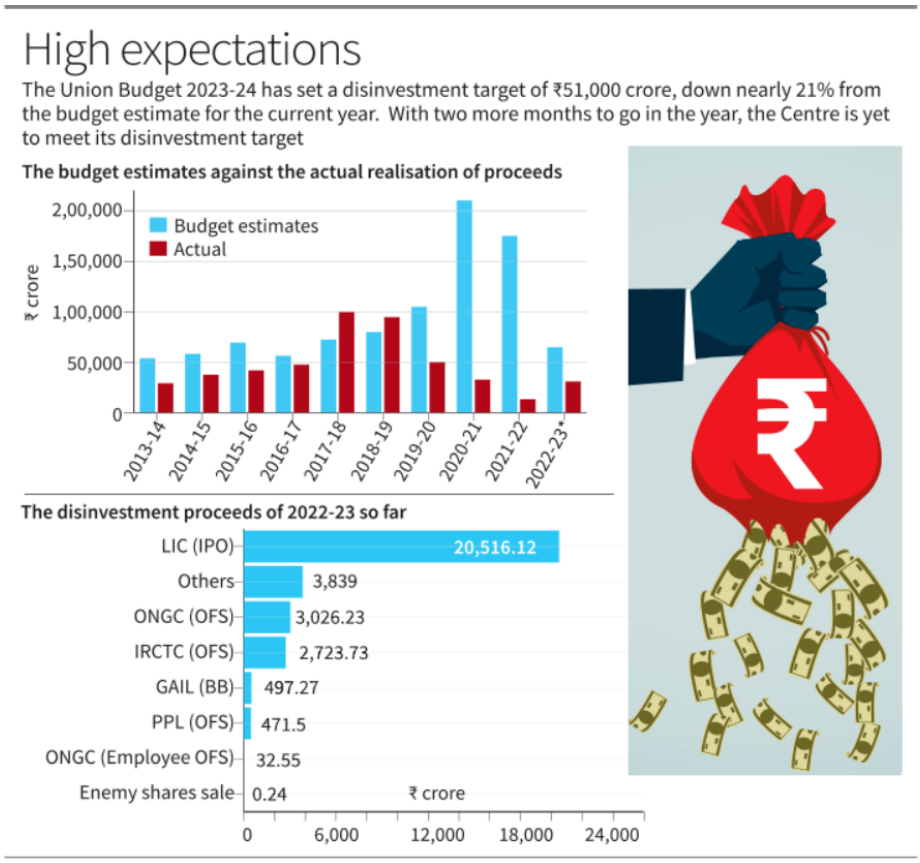

//

- वर्ष 2014 के बाद से सरकार ने अपने विनिवेश लक्ष्यों को दो बार पूरा (लक्ष्य से अधिक) किया है ।
    - वर्ष 2017-18 में सरकार ने 72,500 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 1 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक की विनिवेश प्राप्तियाँ अर्जित कीं और वर्ष 2018-19 में यह आँकड़ा निर्धारित 80,000 करोड़ रुपए लक्ष्य के मुकाबले 94,700 करोड़ रुपए था।
- **सरकार ने अब तक वर्ष 2022-23 के विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है,** अब तक 31,106 करोड़ रुपए प्राप्त किये गए हैं, जिनमें से 20,516 करोड़ रुपए, जो कि बजटीय अनुमान के एक-तिहाई के करीब है, **जीवन बीमा निगम (LIC)** में इसके **3.5% शेयरों के** IPO (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) से आया है।

वर्ष 2023-24 के लिये विनिवेश योजना:

- केंद्र वर्ष 2023-24 में विनिवेश किये जाने वाले **CPSE की सूची में नई कंपनियों को नहीं जोड़ने** की योजना बना रहा है।
- सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के पहले से ही घोषित और नियोजित निजीकरण पर निर्भर रहने का फैसला किया है।
    - इनमें IDBI बैंक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ConCor), NMDC स्टील लिमिटेड, BEML, HLL LIFECARE आदि शामिल हैं।
    - संयोग से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SCI और ConCor के विनिवेश को सरकार ने वर्ष 2019 में मंज़ूरी दी थी लेकिन यह भी

तक नहीं पूरी हो पाई है।

भारत में विनिवेश चुनौतियाँ:

- **राजनीतिक विरोध:** विनिवेश भारत में राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील मुद्दा है, राजनीतिक दल तथा ट्रेड यूनियन अक्सर इस प्रक्रिया के विरोधी रहे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री का विरोध करते हैं।
- **मूल्यांकन के मुद्दे:** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मूल्यांकन एक चुनौती हो सकती है क्योंकि ये उद्यम नौकरशाही और गैर-बाज़ार-उन्मुख संरचनाओं के कारण बाज़ार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- **श्रमिक मुद्दे:** विनिवेश श्रम संबंधी मुद्दों से अछूता नहीं है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में श्रमिकों को इन उद्यमों की बिक्री के बाद नौकरी छूटने या वेतन कटौती का डर बना रह सकता है।
- **खरीदारों से ब्याज की कमी:** कुछ मामलों में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी हेतु खरीदार खोजने के लिये संघर्षरत मालूम पड़ती है, खासकर अगर ये उद्यम वित्तीय रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।
- **विनियामक चुनौतियाँ:** विनिवेश की प्रक्रिया कई प्रकार के विनियमों और अनुमोदन प्रक्रियाओं के अधीन है, जो प्रक्रिया की गति को प्रभावित कर सकती है तथा इसकी जटिलता को बढ़ा सकती है।
- **कानूनी चुनौतियाँ:** विनिवेश की प्रक्रिया को न्यायालयों में भी चुनौती दी जा सकती है क्योंकि वादी बिक्री की वैधता अथवा उन नियमों और शर्तों को चुनौती दे सकते हैं, जिनके तहत इसे आयोजित किया गया था।

आगे की राह

- कुल मिलाकर विनिवेश को भारत में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। राजस्व सृजन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की दक्षता में सुधार लाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा अधिक गतिशील एवं सतत् अर्थव्यवस्था बनाने में मदद के उद्देश्य से भारत में सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम को जारी रखा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2010)

1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना
2. उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना
3. अधिकारी तंत्र की डाउन-साइज़िंग करना
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री/ऑफलोडिंग

उपर्युक्त में से किसका उपयोग भारत में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपायों के रूप में किया जा सकता है?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 3 और 4

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? (2011)

1. सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है ।
2. सरकार अब CPSE के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न. राष्ट्रीय निवेश निधि, जिसमें विनिवेश प्राप्तियाँ पहुँचती हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010)

1. केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश निधि की परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है।

2. राष्ट्रीय निवेश निधि भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है।
3. कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियाँ, निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं।
4. वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्तपोषण करने के लिये प्रयुक्त होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 3 और 4
(d) केवल 3

उत्तर: (c)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/status-and-proceeds-of-disinvestment